

शेखावाटी विरासत एवं विकास समिट

महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

शेखावाटी में विरासत संरक्षण के साथ समग्र विकास कर रही सरकार, शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां और धार्मिक स्थल अमूल्य धरोहर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ सहेज रहे विरासत

हवेली संरक्षण के साथ हेरिटेज टूरिज्म सर्किट किया जा रहा विकसित

अंतरराज्यीय समझौतों से जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा राजस्थान

खरीदने की बजाय अब दूसरे प्रदेशों को दी जा रही बिजली

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार जल संकट से मुक्ति, बेहतर कनेक्टिविटी, हवेलियों के जीर्णोद्धार और पर्यटन को प्रोत्साहित कर शेखावाटी अंचल का समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। शेखावाटी की वीरता, समृद्ध लोक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत राजस्थान की गौरवशाली पहचान है। यहां के पूर्वजों की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ने इस क्षेत्र को देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाई है। यहां की ऐतिहासिक हवेलियां और धार्मिक स्थल अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के विजन के अनुसार राज्य सरकार इसी विरासत को संरक्षित करने के साथ ही उन्हें पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। वहीं, जल-बिजली उपलब्धता, बेहतर सड़क सम्पर्क और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित शेखावाटी विरासत एवं विकास समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से नई पीढ़ी को व्यवसाय एवं उद्योगों से जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थानियों की मेहनत, हुनर और उद्यमशीलता की पहचान पूरी दुनिया में है। युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर उसे उद्यमिता और रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार, सामाजिक संगठनों, उद्यमियों, स्थानीय नागरिकों और प्रवासी



शेखावाटीवासियों के सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

सीमा से लेकर देश की आर्थिक प्रगति में शेखावाटी का अहम योगदान

उन्होंने शेखावाटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों, विरासत संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों और प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा कि शेखावाटी के उद्यमियों और भाभाशाहों का देश की आर्थिक प्रगति में योगदान महत्वपूर्ण है। 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान में भी प्रवासी राजस्थानियों, भाभाशाहों और सामाजिक संस्थाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

जल सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक पहल, शेखावाटी को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी है। इसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने राम जलसेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन्होंने बताया कि राम जलसेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत लगभग एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्यों में से लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इस परियोजना से सिंचाई जल की उपलब्धता के साथ ही पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के माध्यम से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से बाड़मेर और सांचौर सहित जालौर, भीनमाल एवं रानीवाड़ा क्षेत्र को नर्मदा जल समझौते का लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आईजीएनपी, किशाऊ बांध परियोजना, फिरोजपुर फीडर, जवाई जल परियोजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के क्षेत्रों की पेयजल एवं सिंचाई



अपनी विरासत को सहेजने में आएँ आगे

उन्होंने कहा कि शेखावाटी की विरासत केवल हवेलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का एक-एक कण ऐतिहासिक महत्व रखता है। सरकार का प्रयास है कि हवेलियों के मूल स्वरूप और पारंपरिक चित्रकारी को सुरक्षित रखते हुए उन्हें पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों और सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से यहां होटल और पर्यटन उद्योग में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र की 662 हवेलियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और चूरू को शामिल करते हुए हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हवेलियों में चित्रकारी और पारंपरिक शिल्प का कार्य करने वाले स्थानीय कलाकारों एवं कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण देकर इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इससे हमारी पारंपरिक कला सुरक्षित रहेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने शेखवाटी राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी की जा चुकी है। सरकार की प्राथमिकता निवेश को धरातल पर उतारकर उसके लाभ आमजन तक पहुंचाना है। शेखावाटी क्षेत्र में भी निजी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार संभव होगा।

8 दिसम्बर को शेखावाटी हेरिटेज मीट

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विरासत को सहेजकर विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक विरासत, हवेलियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 दिसम्बर को शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश-विदेश में बसे शेखावाटी के प्रवासियों को अपनी मातृभूमि की विरासत के संरक्षण, पर्यटन विकास और निवेश के अवसरों से जोड़ना है। इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा, शेखावाटी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद गोयल, राष्ट्रीय संयोजक हरि शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री गजानंद शर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी गिरधारी कैशेट एवं फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में शेखावाटी अंचल के आमजन उपस्थित रहे।

संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है।

बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर

बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए हैं। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों और होटल संचालकों को भी प्रेरित किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।



रोड कनेक्टिविटी से विकास की रफ्तार हो रही तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में रोड कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य से कोटपुतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और बीकानेर-कोटपुतली

एक्सप्रेस-वे जैसी सड़क परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिनसे सीकर, झुंझुनू और चूरू सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। साथ ही, दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी राजस्थान के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे परिवहन कृषि उत्पादों का विपणन आसान और लागत कम होने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों, धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला: बोले, लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने ही पहुंचाया संस्थाओं को सबसे अधिक नुकसान

एजेंसी। रांची



चिंता रहती है।
विपक्ष पर निशाना और भर्ती घोटाले के खिलाफ जंग

नितिन नवीन ने झारखंड में युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भर्ती घोटालों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कार्यकर्ताओं को स्थानीय मुद्दों, ग्रन्थचार और राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संघर्ष जारी रखना होगा।

झारखंड मेरी जन्मभूमि

नितिन नवीन ने कहा कि झारखंड मेरी जन्मभूमि है और उनकी शिक्षा का बड़ा समय इसी धरती पर बीता है। ऐसे में इस धरती पर किसी कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए घर आने जैसा है। संयुक्त बिहार के समय से

संगठन की ताकत और बिहार-बंगाल से प्रेरणा

नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल और बिहार के संघर्षों से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और भारी कीमत चुकाई। कई कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार तथा सम्मान तक को खो दिया, लेकिन वे संकल्प से पीछे नहीं हटे। इसी प्रकार बिहार में भी पार्टी ने अपने संघर्ष के बल पर स्थिति को मजबूत किया है।

आयुष्मान भारत की शुरुआत भी झारखंड से ही
उन्होंने जनजातीय समाज के गौरव का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने याद दिलाया कि आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी झारखंड की धरती से ही हुई थी।

ही झारखंड क्षेत्र भाजपा के लिए मजबूत गढ़ रहा है। यहां के कार्यकर्ताओं में संघर्ष करने की अपार क्षमता है। जिस दिन कार्यकर्ता पूरी ताकत से कमर कस लेंगे, उस दिन राज्य में भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के प्रथम चरण में सरपंच पदों के लिए मतदान में शाम 6 बजे तक 83.33 प्रतिशत मतदान

जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में 6,19,650 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

झोटवाड़ा में सर्वाधिक 86.51 प्रतिशत तथा किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 80.32 प्रतिशत मतदान दर्ज

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। शाम 6 बजे तक जिले में कुल 7,43,640 मतदाताओं में से 6,19,650 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार जिले में कुल 83.33 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति-वार मतदान प्रतिशत के अनुसार चौमू में 81.53 प्रतिशत, दूदू में 85.35 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 81.25 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 86.51 प्रतिशत, जोबनेर में 83.90 प्रतिशत, किशनगढ़ रेनवाल में 80.32 प्रतिशत, मौजमाबाद में 85.41 प्रतिशत तथा सांभर में 85.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक की रिपोर्ट के



अनुसार चौमू में 1,12,991, दूदू में 56,617, गोविंदगढ़ में 82,772, झोटवाड़ा में 50,737,



जोबनेर में 78,510, किशनगढ़ रेनवाल में 80,445, मौजमाबाद में 80,241 तथा सांभर में 77,337 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खोले के हनुमान जी मंदिर में किए दर्शन



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन और राजस्थान की निरंतर उन्नति की प्रार्थना की।

राजस्थान में ‘प्रोजेक्ट रैक्टर’ की शुरुआत: गिद्धों और शिकारी पक्षियों को बचाने की बड़ी पहल

राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गिद्धों व शिकारी पक्षियों के संरक्षण और निगरानी के लिए ‘प्रोजेक्ट रैक्टर’ की शुरुआत की है।

प्रोजेक्ट रैक्टर के उद्देश्यों और संरक्षण की प्राथमिकताओं पर हुआ मंथन



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान में वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से गिद्धों व अन्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण को लेकर एक नई पहल की गई है। जयपुर वन मुख्यालय में शनिवार को गिद्धों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच मंथन हुआ। इस दौरान ‘प्रोजेक्ट रैक्टर’ के उद्देश्यों और संरक्षण की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान, नियमित निगरानी और सर्माचित प्रयासों से इस संरक्षण रणनीति को मजबूती मिलेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरजितो बनर्जी के मुताबिक, राजस्थान में गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ‘प्रोजेक्ट रैक्टर’ पर मंथन किया गया। इस बैठक में वरिष्ठ वन अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विभिन्न संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट रैक्टर के उद्देश्यों, प्रस्तावित गतिविधियों और शिकारी पक्षियों के संरक्षण की प्रमुख प्राथमिकताओं पर गंभीर चर्चा की गई।

वैज्ञानिक अध्ययनों से पक्षियों के संरक्षण में मिलेगी मदद: भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक ‘सी’ डॉ. आर. सुरेश कुमार और उनकी टीम ने प्रोजेक्ट के उद्देश्यों, प्रस्तावित गतिविधियों व अपेक्षित परिणामों की जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण में पक्षियों की आबादी का व्यवस्थित आकलन करने, उनके आवासमन, आवास के उपयोग और विभिन्न आबादियों के बीच संकट का अध्ययन करने की आवश्यकता बताई गई। इन अध्ययनों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रभावी संरक्षण योजनाएं तैयार करने के लिए बेहतर महत्वपूर्ण माना गया। विशेषज्ञों ने गिद्ध संरक्षण पर रखे अपने विचार: कार्यक्रम में डॉ. क्रिस बोडन ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में अपने वैश्विक अनुभव साझा किए। उन्होंने गिद्धों की आबादी के समक्ष मौजूद खतरों की पहचान करने, नियमित निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लक्षित संरक्षण उपाय विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य राजपाल सिंह, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया और टाइगर फॉर के प्रतिनिधि धर्मेन्द्र खंडाल सहित विभिन्न संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। चर्चा के दौरान संरक्षण संबंधी नीतियों के समाधान के साथ-साथ वन विभाग, अनुसंधान संस्थानों और संरक्षण संगठनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया।

जयपुर में सरपंच चुनाव के बीच चले लाठी-डंडे:खीलवेयर पर वोट देने पहुंचे बुजुर्ग; 11 उम्मीदवारों के नामांकन रिजेक्ट हुए



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। मौजमाबाद के नागौरी मोहल्ले में चुनाव को लेकर लाठी-डंडे चल गए, पुलिस ने मामले को शांत कराया। मौजमाबाद के नागौरी मोहल्ले में चुनाव को लेकर लाठी-डंडे चल गए, पुलिस ने मामले को शांत कराया। जयपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 212 ग्राम पंचायतों में वोटिंग खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे से देर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। अब देर रात तक रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। बता दें कि आज जयपुर जिले की गोविंदगढ़, चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू और मौजमाबाद पंचायत समितियों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 212 सरपंच पदों पर चुनाव लड़ने के लिए 1525 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया में इन सभी 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए 21119 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे, जिनमें से 11 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच में कमी पाए जाने के बाद रिजेक्ट कर दिए। जबकि 583 उम्मीदवार ऐसे रहे, जिन्होंने स्वैच्छा से नाम वापस लेकर मैदान छोड़ दिया था।

राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जयपुर जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

किया मतदाताओं का उत्साहवर्धन

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पंचायती राज आम चुनाव के प्रथम चरण के अंतर्गत सरपंच व पंचों के चुनाव के लिए शनिवार को हुए मतदान प्रक्रिया को पूर्ण स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों के प्रथम चरण के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत समिति चौमूं की ग्राम पंचायत अनंतपुर (जेटपुरा) की बूथ संख्या 68 से 71, ग्राम पंचायत देवपुरा की बूथ संख्या 29 से 31 ग्राम पंचायत जयसिंहपुर के बूथ संख्या 25 से 28 तथा गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मलिकपुर कि बूथ संख्या 37 से 40 तथा बूथ संख्या 41 से 45 तक के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने इस दौरान सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सार्थक अपील भी की।



वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने झोटवाड़ा, सांभर लेक, तथा मौजमाबाद पंचायत समितियों के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर मतदाताओं को मतदान केंद्र पर उपलब्ध बिजली पानी स्वच्छता सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान

राजस्थान- इस महीने के आखिर में बारिश का अलर्ट

चूरू में ओले गिरे, 2 जिलों में बरसात; शहरों का पारा 2 डिग्री तक लुढ़का

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शनिवार को भी रहा। चूरू सहित तीन जिलों में दोपहर बाद मौसम बदला। ओले गिरने के साथ बारिश भी हुई।

बरसात के कारण तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हुई, जिससे रात में हल्की सर्दी रही। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी रही। राज्य में आज से तीन दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि अक्टूबर के अंत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने और उसके असर से राज्य में बारिश होने का अलर्ट है।

3 जिलों में मौसम बदला: शनिवार दोपहर बाद उत्तरी राजस्थान के मौसम में बदलाव हुआ। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में बादल छाए और हवा चली। चूरू में बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश से अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री गिरकर 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिसके कारण यहां दिन में भी हल्की सर्दी रही। अब कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने आज से प्रदेश में मौसम साफ रहने ेका अनुमान जताया है। अगले तीन-चार दिन कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है।

राजस्थान के प्रमुख शहरों में मौसम का हाल

जयपुर: शनिवार दिनभर आसमान में हल्के बादल



रहे, जिससे धूप कमजोर रही। तापमान में मामूली गिरावट होने के बाद यहां अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रात में हल्की हवा चलने से ठंडक रही। मौसम विभाग ने जयपुर में अगले तीन-चार दिन मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। **अजमेर:** शनिवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में गर्मी का असर रहा, जबकि रात में मौसम ठंडा रहा।

अलवर: शनिवार सुबह से ही मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सुबह आसमान में घने बादल छाए रहे, जबकि दोपहर के समय मौसम खुल गया और धूप निकल आई। धूप निकलने के बावजूद गर्मी का असर कम रहा। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। शुक्रवार को हुई बारिश और

ओलावृष्टि के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। **कोटा:** रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। हालांकि, दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। **जोधपुर:** शनिवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान में पिछले कुछ दिनों से कमी आने से रात में हल्की ठंड होने लगी है।

उदयपुर: मौसम में बदलाव के बीच शनिवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट आई, जबकि न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सीकर: शनिवार को दिन में हल्के बादल छाए रहे। सुबह से धूप निकली और बादलों की आवाजाही बनी रही। शाम को हल्की ठंडक का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर में अगले 3 दिन में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर 28 अक्टूबर को जयपुर में जुटेंगे प्रदेशभर के पत्रकार

आईएफडब्ल्यूजे के 77वें स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पर होगा आयोजन, मुख्यमंत्री के नाम सौपेंगे ज्ञापन

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों की लंबित मांगों के समाधान और उनकी आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 28 अक्टूबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से सैकड़ों पत्रकारों के शामिल होने की संभावना है।

आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम बुधवार, 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसकी शुरुआत दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की जाएगी। इसके बाद पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग

राठौड़ ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और आजीविका के संरक्षण के लिए प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान हिंसा, धमकियों, उत्पीड़न और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कानूनी कार्रवाई और पीड़ित पत्रकारों को सुरक्षा देने की



प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, स्वतंत्र, फ्रीलांस और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यरत पत्रकारों को समान कानूनी संरक्षण देने की मांग की। साथ ही पत्रकारों के वेतन, सेवा शर्तों, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी ठोस वैधानिक प्रावधान किए जाने पर जोर दिया।

दिल्ली में पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर जताई चिंता

संगठन ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों के साथ कथित हिंसा, दुर्व्यवहार, हिरासत और पत्रकारिता उपकरणों की जब्ती से जुड़ी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। राठौड़ ने संबंधित मामलों में पारदर्शी जांच और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निकट महिला पत्रकार ऋचा पाराशर के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायत की निष्पक्ष जांच करने तथा संश्लिष्ट साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की भी मांग की।

आजीविका और राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर का मुद्दा

राठौड़ ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा का दायरा केवल शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आजीविका, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पत्रकारों के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारों के कथित दुरुपयोग और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने वास्तविक पत्रकारों की पहचान सुनिश्चित

करने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर गठित करने की मांग भी रखी। उनके अनुसार, यह व्यवस्था पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए तथा इसका उपयोग पत्रकारिता की स्वतंत्रता सीमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

दिल्ली का राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित

राठौड़ ने बताया कि आईएफडब्ल्यूजे की ओर से 28 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम को मौजूदा परिस्थितियों और संबंधित परामर्शों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। अब संगठन की प्रदेश इकाइयां अपने-अपने प्रदेश मुख्यालयों पर स्थापना दिवस मनाएंगी। राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त समारोह इस वर्ष के अंत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने राजस्थान की सभी जिला इकाइयों के पदाधिकारियों, सदस्यों और पत्रकारों से 28 अक्टूबर को जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। राठौड़ ने कहा कि पत्रकारों के अधिकारों, सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा के लिए संगठित प्रयास आवश्यक हैं।

राजस्थान में पंच-सरपंच चुनाव में बंपर Voting, 80.09% हुआ मतदान, चौमूं में मतपेटियां सील करने के दौरान हंगामा

राजस्थान के पाली के रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 56.82% मतदान हुआ।

राजस्थान में पंच-सरपंच के चुनाव

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में शनिवार को पंच-सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक प्रदेश में 80.09 प्रतिशत मतदान

दर्ज किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। कई इलाकों में मतदान का प्रतिशत 90 के पार पहुंचा, जबकि कुछ पंचायत समितियों में वोटिंग अपेक्षाकृत कम रही। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदान के आंकड़ों में बाड़मेर जिले की पंचायत समितियां आगे रहीं। बाड़मेर की मांगटा पंचायत समिति में सर्वाधिक 91.42 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 56.82 प्रतिशत वोट पड़े। दोनों क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत में 34.60 प्रतिशत अंक का अंतर रहा. ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं और अंतिम आंकड़ों में बदलाव संभव है. वहीं चौमूं के मोरीजा ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर मतपेटियां सील करने के दौरान एजेंट को बाहर निकालने का आरोप को लेकर ग्रामीणों के हंगामे के बाद मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी मच गई.

जयपुर में हुआ 86.56 प्रतिशत मतदान : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए शनिवार को मतदान सम्पन्न हुआ. जिले में कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 6 लाख 43 हजार 710 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस प्रकार जिले में कुल 86.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति-वार अंतिम मतदान प्रतिशत के अनुसार चौमूं में 87.19 प्रतिशत, दूदू में 88.66 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 85.70 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 89.70 प्रतिशत, जोबनेर में 85.86 प्रतिशत, किशनगढ़ रेनवाल में 81.53 प्रतिशत, मौजमाबाद में 88.61 प्रतिशत और सांभर में 87.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार चौमूं में 1,20,835, दूदू में 58,812, गोविंदगढ़ में 87,307, झोटवाड़ा में 52,609, जोबनेर में 80,344, किशनगढ़ रेनवाल में 81,653, मौजमाबाद में 83,249 और सांभर में 78,901 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

बाड़मेर में मतदान का सबसे ज्यादा उत्साह : मतदान प्रतिशत के लिहाज से बाड़मेर जिला प्रमुखता से सामने आया. यहां मांगटा पंचायत समिति में 91.42 प्रतिशत मतदान हुआ, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा. रामसर में 90.03 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. चौहटन और सेड़वा में 89.98 प्रतिशत तथा धनाऊ में 89.76 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले की 10 पंचायत समितियों में मतदान प्रतिशत 84.71 से 91.42 के बीच रहा. बाड़मेर की कई पंचायत समितियों में 89 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज होना ग्रामीण मतदाताओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है. गांवों में सरपंच पद के उम्मीदवारों के बीच मुकाबले के बीच मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. बीकानेर और फलोदी में भी 90 प्रतिशत के करीब वोटिंग : बीकानेर जिले की पूगल पंचायत समिति में 90.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. खाजूवाला में 86.79 प्रतिशत और छहरगढ़ में 85.67 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. फलोदी क्षेत्र में भी मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहा. फलोदी पंचायत समिति में 89.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि षटियाली में 88.09 प्रतिशत और आऊ में 87.42 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. इन क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के चयन में सक्रिय भागीदारी निभाई.अलवर में मुबारिकपुर सबसे आगे : अलवर जिले की पंचायत समितियों में मुबारिकपुर में सर्वाधिक 88.58 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. रामगढ़ में 88.43 प्रतिशत और गोविंदगढ़ में 87.46 प्रतिशत वोट पड़े. जिले की छह पंचायत समितियों में मुबारिकपुर मतदान प्रतिशत के मामले में सबसे आगे रहा।

पानीपेच में जाम से आपातकालीन सेवाओं पर संकट, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की राह बाधित होने की चिंता

व्यापारियों का कारोबार प्रभावित, यातायात व्यवस्था सुधारने और मौके पर नियमित पुलिस तैनाती की मांग



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजधानी जयपुर के पानीपेच और आसपास के मांगों पर लगने वाले जाम की समस्या को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने चिंता जताई है। जाम के कारण आमजन और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही बाधित होने की आशंका ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। इसको लेकर लघु उद्योग व्यापार महासंघ, जयपुर के महासचिव मोहम्मद शाहिद खान ने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आपातकालीन वाहनों को मिले प्राथमिकता से रास्ता

मोहम्मद शाहिद खान ने कहा कि आग लगने या किसी गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाने जैसी आपात स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। यदि फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस जाम में फंस जाए, तो सहायता पहुंचने में देरी हो सकती है। इसलिए आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानीपेच क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के लिए प्रभावी योजना तैयार करने की जरूरत है। जाम वाले स्थानों पर यातायात पुलिस की नियमित तैनाती, आवश्यकता के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन और आपातकालीन वाहनों के लिए निर्बाध निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

व्यापारियों को भी उठाता पड़ रहा लुकसान

खान के अनुसार, जाम की समस्या से स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी होती है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार होने से आमजन को राहत मिलने के साथ व्यापारिक गतिविधियां भी सुचारु हो सकेंगी। बसों के संघालन और टहलव की हो जायें

व्यापार महासंघ के महासचिव ने मांग की कि क्षेत्र से गुजरने वाली बसों के निर्धारित मार्ग।

अजमेर में वकीलों के लिए भवन बनाने की मांग उठी

209 दावों के लिए 8.16 करोड़ मंजूर, जोधपुर में राजस्थान बार कौंसिल की बैठक में लिए फैसले

द अनकवर्ड अपडेट

जोधपुर। राजस्थान बार कौंसिल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शनिवार को चेयरमैन योगेन्द्र शक्तावत की अध्यक्षता में वकीलों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। जोधपुर में हुई बैठक में 209 दावों के लिए 8.16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बैठक का मुख्य मुद्दा अजमेर में अधिवक्ता भवन बनाने की मांग रहा। राजस्व मंडल अजमेर में होने से वकीलों को वहां जाना पड़ता है। बार कौंसिल अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मिलकर मुफ्त जमीन और बजट मांगेगा।

209 दावों के लिए 8.16 करोड़ रुपए मंजूर

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष ने कुल 209 दावों के लिए 8.16 करोड़ रुपए मंजूर किए। इनमें 91 मृत्यु दावों के लिए 5.27 करोड़ रुपए, 89 बीमारी दावों के लिए 90.47 लाख रुपए और 29 रिटायरमेंट दावों के लिए 1.99 करोड़ रुपए शामिल हैं। अधिवक्ताओं के नाम बदलने और 'डॉ.' लगाने के आवेदनों को मंजूरी मिली। हरेन्द्र सिनसिनवार की अध्यक्षता में पंजीयन समिति ने 2400 अधिवक्ताओं का पंजीयन किया।

पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के प्रथम चरण में सरपंच पदों के लिए हुआ 86.56 प्रतिशत मतदान

जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में 6 लाख 43 हजार 710 मतदाताओं ने किया मतधिकार का प्रयोग

झोटवाड़ा में सर्वाधिक 89.70 प्रतिशत तथा किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 81.53 प्रतिशत मतदान दर्ज

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए शनिवार को मतदान सम्पन्न हुआ। जिले में कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 6 लाख 43 हजार 710 मतदाताओं ने अपने मतधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार जिले में कुल 86.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति-वार अंतिम मतदान प्रतिशत के अनुसार चौमूं में 87.19 प्रतिशत, दूदू में 88.66 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 85.70 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 89.70 प्रतिशत, जोबनेर में 85.86 प्रतिशत, किशनगढ़ रेनवाल में 81.53 प्रतिशत, मौजमाबाद में 88.61 प्रतिशत तथा सांभर में 87.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार चौमूं में 1,20,835, दूदू में 58,812, गोविंदगढ़ में 87,307, झोटवाड़ा में 52,609, जोबनेर में 80,344, किशनगढ़ रेनवाल में 81,653, मौजमाबाद में 83,249 तथा सांभर में 78,901 मतदाताओं ने अपने मतधिकार का प्रयोग किया।

जयपुर में 1 नवंबर को होगा ‘Samved Jewels’ का भव्य शुभारंभ, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत रहेंगी मौजूद

सीतापुरा स्थित प्रतिष्ठान में होगा आयोजन, शुभारंभ के बाद मीडिया से रूबरू होंगे कंपनी के प्रतिनिधि

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जयपुर में Samved Jewels Pvt. Ltd. की ओर से 1 नवंबर 2026, रविवार को भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया जाएगा। कंपनी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम जयपुर के सीतापुरा स्थित प्रतिष्ठान में होगा। इस विशेष अवसर पर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत की उपस्थिति प्रस्तावित है।

कंपनी के अनुसार, शुभारंभ समारोह के दौरान Samved Jewels की नई शुरुआत और भविष्य की योजनाओं से संबंधित

जयपुर के चौमूं में चुनाव में अफवाह, पुलिस पर पथराव

नागौर में हनुमान बेनीवाल की एक भाभी सरपंच बनी-एक हारी, अजमेर में हार्डवे जाम

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान के 16 जिलों में शनिवार को पहले चरण में पंच-सरपंच के लिए वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक कुल 80.09 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग बाड़मेर की सेड़वा पंचायत समिति में 93.03% और सबसे कम सिरोही की कालिंदी पंचायत समिति में 57.35% हुई है।

जयपुर में चौमूं के मोरोजा ग्राम पंचायत में वोट चोरी के आरोपों को लेकर हंगामा हो गया। आक्रांशित ग्रामीणों ने सामोद पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

तहसीलवार डॉ. विजयपाल विरोही ने बताया- एक एजेंट ने अफवाह फैलाई कि यहां मतपेटी बदली जा रही है। इसके बाद भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद



जयपुर में जमीन के सौदे में 11.11 करोड़ हड़पने का आरोप, बिना पूरा भुगतान किए रजिस्ट्री और पट्टे जारी करवाने का दावा

25.14 बीघा कृषि भूमि का 75:25 प्रतिशत भागीदारी में हुआ था एमओयू, 14 चेक बाउंस होने का आरोप; कंपनी मालिक ने आरोपों को बताया गलत

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जयपुर में जमीन के सौदे के नाम पर 11.11 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवासीय योजना विकसित करने के नाम पर कृषि भूमि का एमओयू किया गया, लेकिन पूरी रकम चुकाए बिना ही जमीन की रजिस्ट्री करवाकर जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से पट्टे जारी करवा लिए गए। मामले में सांगानेर सदर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, संबंधित कंपनी के मालिक ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे अनुचित दबाव बनाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश बताया है। इस मामले को लेकर सांगानेर कोर्ट में भी प्रकरण विचाराधीन बताया गया है।

63 लाख रुपए प्रति बीघा में हुआ था जमीन का सौदा

सांगानेर के वाटिका निवासी चिरंजी लाल (62) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके परिवार की सांगानेर के रामसिंहपुरा में 25.14 बीघा कृषि भूमि है। आरोप के अनुसार, वर्ष 2023 में पवित्र विजय सिंह ने जेडीए से अनुमोदित आवासीय योजना विकसित करने के सिलसिले में उनकी मुलाकात जय इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिमन्यु सिंह से करवाई थी। कंपनी की ओर से आवासीय योजना के लिए करीब 10 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी। इसके बाद नवंबर 2023 में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच एमओयू हुआ। शिकायत के मुताबिक,

कॉलेज स्टूडेंट का किडनैप, 7 लाख की मांगी फिरोती: क्रिप्टो ट्रेडिंग में फंसा, 10 दिन बंधक बनाकर पीटा, 2 गिरफ्तार

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जयपुर में कॉलेज स्टूडेंट को किडनैप कर फिरोती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के 7 लाख रुपए की वसूली के लिए स्टूडेंट को 10 दिन तक फ्लैट में बंधक बनाकर पीटा। फिर स्कॉर्पियो में डाल कर हरियाणा ले गए। पीड़ित नील किशोर घेंटिया(23) नासिक (महाराष्ट्र) का निवासी है और जयपुर से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। प्रताप नगर थाना पुलिस ने शनिवार तड़के भिवानी में दबिश देकर स्टूडेंट को मुक्त कराया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नवीन नायक (24) और भागीरथ उर्फ मंगल (28) भिवानी (हरियाणा) के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर दिया था पैसा

डीसीपी (ईस्ट) रंजिता शर्मा ने बताया- तकनीकी इनपुट और मोबाइल लोकेशन की मदद से आरोपी



जमीन का सौदा 63 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से तय हुआ था। साथ ही विकसित योजना में हिस्सेदारी 75:25 प्रतिशत के अनुपात में निर्धारित की गई थी।

पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद रजिस्ट्री करवाने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जेडीए में योजना के अनुमोदन से संबंधित कार्रवाई के लिए अभिमन्यु सिंह ने अपने ड्राइवर भानू प्रताप सिंह के पक्ष में बेचान संबंधी पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई। इसके बाद जेडीए में योजना का प्लान पेश कर 90-ए की कार्रवाई करवाई गई। आरोप है कि मई 2024 में उनकी जानकारी और सहमति के बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ड्राइवर के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री अभिमन्यु सिंह के नाम करवा दी गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस प्रक्रिया में जमीन के पूरे सौदे की रकम का भुगतान नहीं किया गया।

15.84 करोड़ देने थे, 4.73 करोड़ ही मिले

चिरंजी लाल के अनुसार, जमीन के एवज में कुल 15.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन उन्हें केवल 4.73 करोड़ रुपए ही मिले। इस



नवीन नायक (24) और भागीरथ उर्फ मंगल (28) निवासी भिवानी हरियाणा को अरेस्ट किया है। वादात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो जब्त की है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूएसडीटी ट्रेडिंग करता है। टेलीग्राम एप के जरिए यूएसडीटी पैनल चलाने वाले रजत नाम के लड़के से उसकी जान-पहचान हुई। 5 अक्टूबर को रजत ने यूएसडीटी में पैसा लगाने की कहकर मिलने बुलाया। वहां नवीन ने यूएसडीटी

तरह करीब 11.11 करोड़ रुपए बकाया रहने का आरोप है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि पूरी रकम चुकाए बिना और उनकी सहमति के बिना जमीन पर प्लॉट बेच दिए गए तथा जेडीए से पट्टे भी जारी करवा लिए गए। जमीन खरीदने के एवज में दिए गए 14 चेक बैंक खाते बंद होने के कारण बाउंस होने का आरोप भी लगाया गया है।

कंपनी मालिक ने आरोपों को बताया गलत

दूसरी ओर, जय इंफ्राटेक कंपनी के मालिक ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि कंपनी पर अनुचित दबाव बनाने और ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलने के उद्देश्य से आरोप लगाए जा रहे हैं। कंपनी पक्ष के अनुसार, मामले को लेकर सांगानेर कोर्ट में केस चल रहा है और सदर थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में जमीन के एमओयू, भुगतान, चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और जेडीए से जारी पट्टों से जुड़े दस्तावेज जांच के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। आरोपों की पुष्टि और जिम्मेदारी तय होना पुलिस जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।



रुपए न मिलने पर आरोपियों ने नील को फ्लैट में बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया। 10 दिन तक जयपुर में रखने के बाद 15 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे आरोपी उसे काली स्कॉर्पियो में डालकर भिवानी स्थित अपने गांव ले गए। वहां पहली मंजिल के कमरे में बंद कर मारपीट की और नील के पिता को वाट्सएप कॉल कर 7 लाख रुपए की फिरोती मांगी। रकम न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी।

LMB और गुड़ मिश्री मिष्ठान के प्रोडक्शन हाउस पर छापा:मिठाई के पैकेट पर 1 नवंबर की मैनुफेक्चरिंग डेट मिली, विभाग ने 35 हजार जुर्माना लगाया



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। त्योहारों पर अगर आप भी फेमस दुकानों से मिठाईयां खरीद रहे हैं तो संभल जाएं। दरअसल, जयपुर में लीगल मेट्रोएलॉजी डिपार्टमेंट की कार्रवाई में शहर के दो प्रतिष्ठित दुकानों पर छापे मारे गए, इनमें गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड और लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर छापा मारा गया।

इस दौरान टीम को गुड़ मिश्री के भंडार पर मिठाई की निर्माण तारीख 1 नवंबर 2026 और उपयोग की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 छपी थी। यह कार्रवाई 23 अक्टूबर को की गई, जबकि 22 अक्टूबर को लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर छापा मारा गया। जहां पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने, पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य, शुद्ध मात्रा, निर्माण तिथि और बेस्ट बिफोर जैसी आवश्यक जानकारी अंकित नहीं करने पर दोनों प्रतिष्ठानों पर 35,हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

विधिक मापविज्ञान विभाग की टीम ने विधिक मापविज्ञान अधिकारी रिपुदमन सिंह और निहाल वशिष्ठ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। काजू-पतीसा मिठाई के पैकेट पर मिली आगे की डेट

टीम ने जयपुर के कानोता स्थित गुड़ मिश्री प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारा। वहां काजू-पतीसा मिठाई का पैकेट मिला, जिस पर मिठाई की निर्माण तारीख 1 नवंबर 2026 और उपयोग की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 छपी थी। इसके अलावा प्रतिष्ठान में पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और गुड़ चक्र मिठाई, काजू रोल मिठाई के पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (रू०००), मात्रा (वजन) जैसी जानकारी नहीं थी। इस पर फर्म के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया ।

LMB पर 15 हजार का जुर्माना

टीम ने जौहरी बाजार स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। यहां टीम को प्रतिष्ठान में पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इसके साथ ही मंगोड़ी, पापड़, खाखरे, सोहन पापड़ी और पेठे के पैकेटों पर MRP, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थी। संबंधित उत्पादों को आवश्यक जानकारी अंकित नहीं होने पर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करके 15 हजार का जुर्माना लगाया। है।

देखिये

TNI आवाज़

पर हमारे खास कार्यक्रम

रमाकान्त गोस्वामी के साथ...

TNI मुलाकात

देश की जानी-मानी हस्तियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और समाज के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से खास बातचीत।

उम्मीद की एक नई रोशनी

संघर्ष, सफलता और प्रेरणा की ऐसी कहानियां जो बदल रही हैं समाज की सोच।

THE UNCOVERED UPDATE

हर उस खबर की पड़ताल, जो सुर्खियों के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाती है।

राजस्थान की राजनीति

राजस्थान की राजनीति, सत्ता, विपक्ष, चुनाव और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का सटीक विश्लेषण और एक्सक्लूसिव कवरेज।

खबरों से आगे, सच्चाई के साथ

अब उपलब्ध 16+ प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म पर

JioTV

Jio Fiber

TATA PLAY

VI TV movies & TV

MXPLAYER

dailyhunt

paytm LIVE TV

shemaro TV

DTH LIVE TV

और भी कई प्लेटफॉर्म पर

www.tniawaaz.in

f y t i /tniawaaz

DOWNLOAD NOW TNI AWAAZ APP

दिल्ली में बैठे बैठे मोदी ने इराक़ में कर दिया खेल, भारत के पास अब तेल ही तेल



नीरज कुमार दुबे

देखा जाये तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग और आम आदमी के जीवन में पेट्रोलियम की अहम भूमिका है। ऐसे में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि भी भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव डाल सकती है।

दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है, वेनेजुएला से कितना तेल खरीदेगा और अमेरिकी दबाव के आगे भारत अपने फैसले बदलेगा या नहीं। लेकिन इस पूरे शोर-शराबे के बीच एक बड़ा सवाल जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है कि इराक़ से भारत कितनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इस खरीद से अपने आर्थिक हितों को कैसे साध रहा है? देखा जाये तो रूस और वेनेजुएला के तेल पर दुनिया बहस करती रहे, लेकिन भारत की असली रणनीति समझनी है तो इराक़ के साथ उसके तेल कारोबार पर नजर डालनी होगी। यही वह मोर्चा है, जहां भारत अपनी जरूरत, बाजार और कीमत के हिसाब से फैसले लेकर दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी के दबाव से नहीं, बल्कि देश के हितों से तय होती है।

इराक़: भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा स्तंभ
देखा जाये तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग और आम आदमी के जीवन में पेट्रोलियम की अहम भूमिका है। ऐसे में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि भी भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव डाल सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में इराक़ ने भारत को 4.711 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल उपलब्ध कराया। यह भारत के कुल तेल आयात के मूल्य का लगभग 19.16 प्रतिशत था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इराक़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि इराक़ भारत के लिए कोई मामूली या वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता नहीं है। वह भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। भारतीय तेल कंपनियां इराक़ से नियमित रूप से तेल खरीदती हैं और इस व्यापार के माध्यम से दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी मजबूत होते हैं।

अक्टूबर 2026 की खरीद-व्यापार चर्चा में आया इराक़ का तेल?

इराक़ से भारत की खरीद का महत्व हाल के घटनाक्रमों से और बढ़ गया है। 22 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में भारत ने इराक़ से प्रतिदिन लगभग 8.30 लाख बैरल तेल आयात किया, जबकि अगस्त में यह मात्रा लगभग 1.71 लाख बैरल प्रतिदिन थी। इसी दौरान भारत का रूस से तेल आयात लगभग 14 प्रतिशत घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। यह बदलाव बताता है कि भारत की तेल खरीद किसी एक राजनीतिक समीकरण से तय नहीं होती। जब मध्य-पूर्व का तेल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होता है, तो भारतीय रिफ़ाइनरियां उसकी ओर रुख कर सकती हैं। रूस का तेल भी भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण बना रहता



है, लेकिन खरीद का फैसला कीमत, परिवहन खर्च, उपलब्धता और रिफ़ाइनरी की जरूरतों के आधार पर होता है। इस रणनीति का एक और उल्लेखनीय उदाहरण सामने आया। इसी महीने की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इराक़ के बसरा टर्मिनल से लगभग 20 लाख बैरल बसरा मीडियम क्रूड की एक खेप खरीदने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट में इस खरीद के लिए दुबई के तेल मूल्य से 32 डॉलर प्रति बैरल कम कीमत का उल्लेख किया गया। यह उदाहरण उस मूल सिद्धांत को सामने लाता है जिस पर भारत की ऊर्जा रणनीति आधारित होनी चाहिए। यानि जहां बेहतर आर्थिक शर्तें मिलें, वहां से तेल खरीदने के विकल्प खुले रखे जाएं।

वैश्विक बाजार पर क्या पड़ता है इसका असर?
देखा जाये तो तेल बाजार में भारत जैसे बड़े खरीदार का निर्णय केवल उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। भारत प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का आयात करता है। इसलिए यदि भारतीय कंपनियां रूस के बजाय इराक़ या दूसरे मध्य-पूर्वी उत्पादकों से अधिक तेल खरीदती हैं, तो अलग-अलग तेल ग्रेड की मांग, व्यापारिक प्रवाह और क्षेत्रीय मूल्य प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। सितंबर 2026 में मध्य-पूर्व से भारत का कुल तेल आयात बढ़कर लगभग 28 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। यह भारत के कुल तेल

आयात का लगभग 54 प्रतिशत था। बताया जा रहा है कि मध्य-पूर्वी तेल की बेहतर उपलब्धता और रूसी तेल पर घटते मूल्य-लाभ ने इस बदलाव में भूमिका निभाई। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि इराक़ से ज्यादा तेल खरीदते ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें गिर जाएंगी। वैश्विक कीमतों पर ओपेक की उत्पादन नीति, युद्ध, समुद्री परिवहन, मांग और आपूर्ति जैसे कई कारक असर डालते हैं। लेकिन भारत का विविध स्रोतों से खरीदना आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अपने लिए बेहतर सौदे हासिल करने में मदद कर सकता है। यहां सवाल उठता है कि इस सबसे भारत को क्या फायदा हो सकता है? देखा जाये तो पहला फायदा है आयात लागत में बचत। अगर किसी खेप का वास्तविक पहुंच-मूल्य अन्य विकल्पों की तुलना में कम पड़ता है, तो भारतीय कंपनियों का खर्च घट सकता है। इसका लाभ रिफ़ाइनरियों के मुनाफ़े और व्यापक अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कम कीमत का लाभ पेट्रोल-डीजल के खुदरा दामों में कितना पहुंचेगा, जो करों, रिफ़ाइनिंग लागत और सरकारी मूल्य निर्धारण जैसे दूसरे कारकों पर भी निर्भर करता है। दूसरा फायदा है रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत को रूस, इराक़, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और जरूरत

के अनुसार अन्य उत्पादकों से तेल खरीदने के विकल्प बनाए रखने चाहिए। इससे किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है और प्रतिबंधों या आपूर्ति संकट की स्थिति में विकल्प उपलब्ध रहते हैं। तीसरा फायदा है भारत की सौदेबाजी की ताकत। जब भारतीय रिफ़ाइनरियां कई बाजारों से खरीद सकती हैं, तो किसी एक आपूर्तिकर्ता की शर्तों को स्वीकार करना उनकी मजबूरी नहीं रह जाता। लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा, तेल की गुणवत्ता, परिवहन बीमा और भुगतान व्यवस्था का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा, इराक़ से प्रतिस्पर्धी शर्तों पर तेल खरीदना और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत के हितों को सर्वोपरि रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा रणनीति का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक है। दुनिया भर की सरकारें तेल की बढ़ती कीमतों और उसके आर्थिक बोझ से जूझ रही हैं, वहीं भारत ने अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतों में लगभग स्थिरता बनाए रखकर आम जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। रूस हो, इराक़ हो या कोई दूसरा तेल उत्पादक देश, भारत का जोर इस बात पर रहा है कि तेल जहां से भी मिले, उसकी खरीद देश के आर्थिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जाए। यही मोदी सरकार की रणनीति की खासियत है कि वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए बेहतर विकल्प तलाशना और अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव को सीधे आम आदमी की जेब पर हावी न होने देना। जब दुनिया के कई देश महंगे तेल की चुनौती से जूझ रहे हैं, तब भारत में कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखना मोदी सरकार की ऊर्जा नीति की एक अहम उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है। हालांकि इराक़ से तेल खरीदने में जोखिम भी हैं। खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और आपूर्ति में संभावित बाधाएं आयात के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। इसलिए सस्ता तेल तभी वास्तविक रणनीतिक लाभ है, जब उसकी आपूर्ति भरोसेमंद और आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी हो। बहरहाल, दुनिया भारत की रूस से तेल खरीद पर नजर रखे या वेनेजुएला से संभावित खरीद पर बहस करे, भारत की ऊर्जा नीति का मूल्यांकन व्यापक तस्वीर के आधार पर होना चाहिए। इराक़ से 4.711 करोड़ टन वार्षिक तेल आपूर्ति और सितंबर 2026 में रहां से आयात में आई तेज बढ़ोतरी यह दिखाती है कि मध्य-पूर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कितनी अहम भूमिका निभाता है। यदि मोदी सरकार और भारतीय तेल कंपनियां प्रतिस्पर्धी कीमतों, सुरक्षित आपूर्ति और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को एक साथ ध्यान पाती हैं, तो यह व्यावहारिक कूटनीति की बड़ी सफलता होगी।

संपादकीय

पोषण के भ्रामक दावे

कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग व विज्ञापनों के खेल से भारत में बच्चों के विकास के लिए जरूरी पोषक पदार्थों को बेचने का उपक्रम देश में दशकों से चला आ रहा है। इस प्रचार के खेल में फिस्मी व स्लेपर की दुनिया की हस्तियां मोटी रकम लेकर शामिल हो जाती हैं। विडंबना यह है कि देश का आम उपभोक्ता देशी-विदेशी खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के उन दावों पर भरोसा कर लेता है, जिनमें बच्चों के तेज विकास, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा दिमाग तेज करने के वादे किए जाते रहे हैं। लेकिन वास्तव में माता-पिता को इन दावों के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने चाहिए, न कि लुभावने विज्ञापन। शिशुओं के विकास के लिए बनाए गए फार्मूले और कॉम्प्लान से संबंधित दावों को लेकर नेस्ले इंडिया और जाइडस वेलेनेस को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई द्वारा नोटिस जारी किए गए, जिसने पोषण संबंधी दावों की विश्वसनीयता और सख्त नियामक निगरानी की आवश्यकता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियामक ने कॉम्प्लान के शिशुओं के तीव्र गति से विकास और एकाग्रता, स्मृति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित लाभ जैसे दावों पर सवाल उठाए हैं। नियामक ने नेस्ले को उसके शिशु आहार के फार्मूले में खास प्रोटीन की पाचन क्षमता और मां के दूध के समान रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक लाभों को प्रमाणित करने के लिए कहा है। निस्संदेह, उत्पाद खरीदते समय ऐसे दावे माता-पिता के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से जब बच्चे के विकास को लेकर चिंताएं परिवार को बेहतर पोषण के वादों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इस मामले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा ऑनलाइन प्रचार की भी जांच की गई, जिसमें शिशु आहार फार्मूला उत्पादों की गुणवत्ता की रैंकिंग की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि इसके उपयोग से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क के विकास और पाचन में लाभ मिलता है। आमतौर पर ऐसे प्रचारक मोटी फीस लेकर उपभोक्ताओं को ठेस पहुंचाने का ही काम करते हैं।

निस्संदेह, इस प्रकरण के बाद डिजिटल विज्ञापनों के नियमन की बढ़ती चुनौती भी सामने आती है। दरअसल, ऐसे भ्रामक व्यावसायिक प्रचार से कभी-कभी वास्तविक लाभ देने वाली सलाह होने का भ्रम भी पैदा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 'शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम' के तहत लगाई गई पाबंदियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका मकसद शिशुओं को मां का दूध देने की स्वास्थ्यकारी प्रथा को अनुचित व्यावसायिक प्रभावों से होने वाले नुकसान से बचना है। वैसे देखें तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिए गए ये नोटिस मुनाफे के लिए किए जा रहे किसी गलत कार्य के अंतिम निष्कर्ष नहीं कहे जा सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकरण में कंपनियों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर, उनके ढढ़-चढ़कर किए जाने वाले दावों की जांच विश्वसनीय सबूतों और नियमों के आधार पर ही की जानी चाहिए। हालांकि, देश के नियामकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना तार्किक आधार वाले या गुमराह करने वाले दावों को उत्पाद बनाने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत सुधार जाए। वहीं दूसरी ओर, नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादकों पर उचित कार्रवाई की जाए। वैसे तो हमारे देश में आमतौर पर खाद्य उत्पादों के लेबल और विज्ञापन ही अक्सर उपभोक्ताओं के लिए जानकारी के मुख्य स्रोत होते हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों व अशिक्षित लोगों में यह समस्या ज्यादा होती है। इसलिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को अपनी जांच-पड़ताल सख्ती से करनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रवर्तन एजेंसियों के नतीजे सामने आने पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही, भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माता किसी उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले अपने दावों को सच्चाई की कसौटी पर सही साबित करे। निश्चित रूप से पोषण संबंधी मार्केटिंग का मकसद सही जानकारी देना होना चाहिए, न कि लोगों को गुमराह करना।

सूक्ति

जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त वस्तु के लिए सम रहता है, वह संतुष्ट कहा जा सकता है।

— महोपनिषद

जल से शरीर शुद्ध होता है, मन से सत्य शुद्ध होता है, विद्या और तप से भूतात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है।

— मनुस्मृति

81 साल बाद भी अधूरी है संयुक्त राष्ट्र की शांति-प्रतिज्ञा



योगेश कुमार गोयल

बदलती दुनिया में अप्रासंगिक होता संयुक्त राष्ट्र...

दुनिया के 50 देशों ने वर्ष 1945 में मिलकर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंतराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना का विचार उभरा था, जो पांच राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा आठ यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ था। उस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया था, जिसमें लोग शांति और सुरक्षा के साथ भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें। उसके

बाद 1944 में सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकों के आयोजन के बाद एक शांतिरक्षक वैश्विक संस्था बनाने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच 1945 में बातचीत हुई और 26 जून 1945 को सभी 50 देशों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' मनाया जाने लगा। अंतराष्ट्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को इतनी शक्तियां प्रदान की गई कि वह अपने सदस्य देशों की सेनाओं को विश्व शांति के लिए कहीं भी तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही दुनिया के अनेक देश इसके साथ जुड़ते गए और 50 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस वैश्विक संघ के सदस्य देशों की संख्या अब 193 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम, जिसकी द्वितीय विश्वयुद्ध में अहम भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सभी देशों के बीच मित्रवत संबंध कायम करना, अंतराष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, निर्धन तथा भूख लोगों की सहायता करना, उनका जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों से लड़ना इत्यादि शामिल हैं और इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। हालांकि विडम्बना है

कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के इन 81 वर्षों में यह वैश्विक संस्था अब धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगी है। दरअसल बीते 81 वर्षों से अंतराष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, हथियार, मीडिया, समाज, मुद्रा तथा समाज से संबंधित तमाम नीतियां इसके पांच स्थायी सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांस के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही निर्धारित की जाती रही हैं, जिस कारण ऐसी नीतियों का खामियाजा भारत के अलावा जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई अन्य देशों को भुगताना पड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता के लिए तमाम मानदंडों को पूरा करने के बाद भी दशकों से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशकों में विश्व के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने और तमाम वैश्विक समीकरण पूर्ण रूप से बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले पांचो स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपने वीटो अधिकार और स्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति है लेकिन चीन को खासकर एशिया से वीटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, जहां स्थायी सदस्यता के दोनों दावेदारों (भारत और जापान) पर वह विभिन्न कारणों से संदेह करता है। भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर

दिया था, आज वही चीन भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। भारत चीन के वीटो पावर के कारण ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते। आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देशों द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्ताव भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए अनेक देशों द्वारा इसमें सुधार किए जाने की मांग बीते कई वर्षों से निरंतर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी की वकालत करते हुए कह चुके हैं कि नई ताकतों को केन्द्रीय भूमिका में लाए बिना दुनिया की यह सबसे बड़ी पंचायत स्वयं से की जाने वाली अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाएगी। दुनिया के कई देश बार-बार कहते रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब पुराना पड़ चुका है और इसकी स्थापना के समय जो परिस्थितियां थी, वे अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती है तो कालांतर में यह महत्वहीन होती चली जाएगी। रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इजरायल-फिलिस्तीन अथवा अमेरिका-ईरान युद्ध, इन संघर्षों में दोनों ही पक्षों के हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं, लाखों की आबादी पलायन की त्रासदी से जूझ रही है, शहर के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन संघर्षों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका है।

WHERE STYLE MEETS IDENTITY

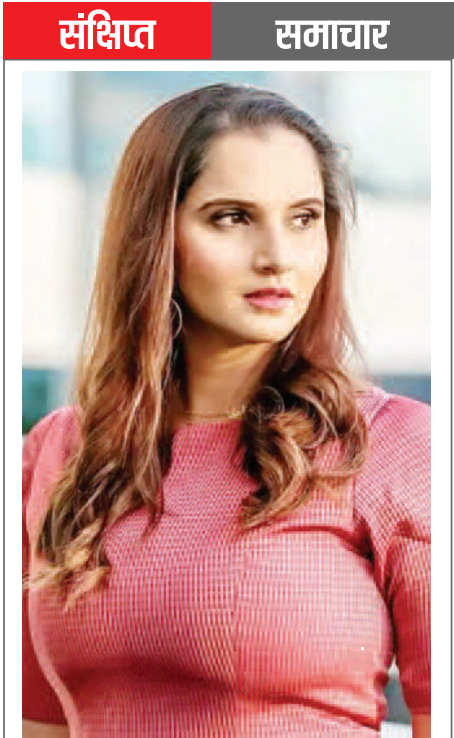
लाइफस्टाइल की दुनिया, अब एक नए अंदाज़ में!

FASHION • BEAUTY • HEALTH • FITNESS • TRAVEL • LUXURY LIFESTYLE

लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरों, स्टोरी, विज्ञापन एवं सहयोग के लिए संपर्क करें

89468 40063

www.urbanvogue.net



सानिया ने की धमाकेदार वापसी

मुंबई । टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पॉडकास्ट ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ के दूसरे सीजन के साथ वापसी की है। खेल, एंटरटेनमेंट और बेबाक बातचीत को एक साथ लाने वाले इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में एक्टर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल नजर आएंगे, जो अपने रिश्ते, शादी और साथ काम करने को लेकर खुलकर बात करते दिखेंगे। पॉडकास्टर के तौर पर अपने सफर के बारे में बात करते हुए सानिया मिर्जा ने कहा, ‘जब मैंने पहली बार पॉडकास्टिंग में हाथ आजमाया, तो मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इसमें कितना मजा आएगा, लेकिन समय के साथ-साथ मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बातचीत और लोगों को उनकी इमेज से अलग जानना कितना मनोरंजक होता है। सानिया मिर्जा ने दूसरे सीजन की वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए बताया, ‘पहले सीजन की सफलता और दर्शकों के रिसॉन्स ने मुझे सीजन-2 के साथ वापस आने की और बड़ी वजह दे दी। मैंने सालों तक टेनिस कोर्ट पर धमाल मचाया है और अब एक पॉडकास्टर के तौर पर अपनी इस नई पारी को एन्जॉय कर रही हूँ। इस सीजन में हमारे पास शानदार लाइनअप है और मैं दर्शकों के साथ इन बातचीतों को देखने के लिए उत्सुक हूँ।’ शो का पहला एपिसोड सानिया के सोनाक्षी और जहीर के साथ पिकलबॉल खेलने से शुरू होगा, जिसमें कपल के सात साल के रिश्ते पर बातचीत होगी। अभिनेत्री सोनाक्षी और उनकी पति जहीर इकबाल साल 2022 में फिल्म ‘डबल एक्सस’ में साथ नजर आए थे और साइकोलॉजिकल/रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ‘तू है मेरी करिण’ में साथ काम किया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। अभिनेत्री सोनाक्षी ने जहीर इकबाल के साथ स्क्रीन शेयर करने के बारे में कहा, ‘मेरे लिए ऑन स्क्रीन रोमांस करना सबसे मुश्किल काम है।

वर्मा जी ने लगाया भारत को जीत का तिलक

रेड्डी ने दिया साथ, क्राइस्टचर्च में टीम इंडिया की मौज

नई दिल्ली, एजेंसी। तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी की दमदार पारी की वजह से भारत ने शनिवार को न्यूजीलैंड के हाथों से जीत छीन ली है। भारत ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फिलिप्स और जैकब्स की दमदार पारियों की वजह से भारत के सामने 181 रनों का लक्ष्य रखा था, जवाब में तिलक और नितीश रेड्डी के नाबाद साझेदारी की वजह से भारत ने आखिरी ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड की शुरुआत रही खराब

इससे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी। टिम साइफर्ट सिर्फ सात रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद फिन एलन को प्रिंस यादव ने बोल्ड कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो 6 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए। भुवी ने चार साल बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए विकेट निकाला।

फिलिप्स-जैकब्स की दमदार पारी
पहले मैच की तरह एक बार फिर ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स ने टीम के लिए शानदार पारी खेली। फिलिप्स और जैकब्स के बीच चौथे विकेट के लिए 76 गेंदों में 116 रनों की शानदार साझेदारी हुई। फिलिप्स ने 43 गेंदों में चार चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत 70 रनों की पारी खेली। वहीं जैकब्स ने पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 46 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 180 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। भारत की ओर से सबसे ज्यादा दो विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए।



नई दिल्ली । भारत ने दूसरे पुरुष ब्लाईड क्रिकेट एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 15 से 20 नवंबर तक बांग्लादेश के ढाका में आयोजित होगा। मौजूदा चैंपियन भारत, एक दशक के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस टूर्नामेंट में अपना खिताब का बचाव करने उतरेगा। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाईड इन इंडिया (सीएबीआई) ने 10 दिनों के गहन चयन और कोचिंग कैंप के बाद इस टीम की पुष्टि की, जिसमें 24 संभावित खिलाड़ी शामिल थे। बांग्लादेश में होने वाले इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए रवाना होने से पहले, चुने गए खिलाड़ी दिल्ली एनसीआर में एक महीने के तैयारी कैंप में हिस्सा लेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, फिटनेस, कंडीशनिंग और मैच की रणनीति पर ध्यान दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों का उनके प्रदर्शन, फिटनेस स्तर, तकनीकी कौशल और समग्र तैयारियों के आधार पर आकलन किया गया। बी1 श्रेणी में नरेश तुमदा, संजय कुमार शाह, देबराज बेहरा, अशोक रेड्डी, प्रवीण कुमार शर्मा और मुकेश कुमार रावत को चुना गया है। बी2 श्रेणी में दुन्ना वेंकटेश्वर राव, रणवीर सिंह, लोकेशा, मनीष कुमार और नकुला बडनायक शामिल हैं। वहीं, बी3 श्रेणी में दुर्गा राव टोम्पाकी, सुनील रमेश, सुखराम माझी, ए. रवि, दिनेश रथवा और दीपक को टीम में जगह मिली है। सीएबीआई के चेयरमैन डॉ. महामेश जी. किवादासनवर ने चुने गए खिलाड़ियों को बधाई दी और उनकी तैयारियों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, ‘पुरुष ब्लाईड



क्रिकेट एशिया कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए 17 खिलाड़ियों को बधाई। हर खिलाड़ी ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमें उम्मीद है कि वे भारत की

बायर्न म्युनिख के मैनेजर विंसेंट कॉम्पनी हुए बेहोश, अस्पताल में भर्ती

म्युनिख। म्युनिख में ट्रेनिंग सेशन के दौरान बायर्न म्युनिख फुटबॉल क्लब के मैनेजर विंसेंट कॉम्पनी बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। क्लब ने पुष्टि की है कि आगे की जांच के लिए वह अभी मेडिकल देखरेख में रहेंगे। बायर्न ने एक बयान में कहा, एफसी बायर्न की एमेच्योर टीम की ट्रेनिंग के दौरान विंसेंट कॉम्पनी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी। फर्स्ट-टीम के कोच उस समय दूसरी टीम का सेशन देख रहे थे। कॉम्पनी का अस्पताल में पूरा चेकअप होगा और वह मेडिकल देखरेख में रहेंगे। फिलहाल, उनका कोचिंग स्टाफ ट्रेनिंग और मैच से जुड़े कामकाज संभालेगा।

यह घटना बुधवार को आर्सेनल के खिलाफ बायर्न के यूईएफए चैंपियंस लीग मैच से कुछ दिन पहले हुई है, जब कॉम्पनी ने अपने पैर और कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी। माना जा रहा है कि यह तकलीफ उन्हें हुए किसी वायरस संक्रमण से जुड़ी है। बायर्न म्युनिख के सहायक कोच आरोन डैक्स ने कॉम्पनी की जगह प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मैनेजर को ठीक होने के लिए समय चाहिए। डैक्स ने कहा, यह बस एक वायरस है।

अनाहत को मिली हार

सिलिकॉन वैली ओपन : सेमीफाइनल में सफर हुआ समाप्त, मलेशिया की शिवसांगरी ने दी शिकस्त

रेडबुल सिटी। सिलिकॉन वैली ओपन के सेमीफाइनल में मलेशिया की शिवसांगरी सुब्रमण्यम से हारकर भारतीय स्टार अनाहत सिंह का सफर समाप्त हो गया। अनाहत को शिवसांगरी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत सिंह ने मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ जोरदार शुरुआत की और पहला गेम 11-5 से जीत लिया। हालांकि, इसके बाद सुब्रमण्यम ने अपने खेल का स्तर बढ़ाया और 37 मिनट तक चले मुकाबले को 11-5, 6-11, 4-11, 7-11 से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह अनाहत की मलेशियाई खिलाड़ी से कुल मिलाकर चौथी और प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन (पीएसए) टूर पर तीसरी हार थी।

अनाहत के लिए शानदार रहा साल

अनाहत के लिए साल 2026 बेहद खास रहा है। उन्होंने 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स का टाइटल जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर पदक जीतकर इस इवेंट में पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था। अनाहत ने इससे पहले हांगझोऊ में 2023 एशियन गेम्स में विमेंस टीम और मिक्स्ट डबल्स कॉम्पिटिशन में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 18 साल की अनाहत का नाम स्क्वैश खिलाड़ी के तौर पर वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को भविष्य में वैश्विक मंचों पर उनसे करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद है। सेमीफाइनल से बाहर होने के बावजूद, सिलिकॉन वैली में अनाहत के प्रदर्शन ने इंटरनेशनल सर्किट पर उनके बढ़ते कद को दिखाया। वर्ल्ड नंबर 15 अनाहत ने इस इवेंट में आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन टॉप सीड एल शेरबिनी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हुए बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद उन्होंने मिश्र की छठी सीड सलमा हैनी को हराया।

मेसी का सम्मान

स्पेन ने अर्जेंटीना के पूर्व कप्तान को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस अवॉर्ड दिया, हुआ जोरदार स्वागत

ओवेएदो। अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनल मेसी का स्पेन में जोरदार स्वागत हुआ। ऑलिंपिडों में 2022 फीफा विश्व कप विजेता को देखने सैकड़ों प्रशंसक पहुंचे, जहां उन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। ओलंपिक्स डॉट कॉम के अनुसार, इंटर मियामी के फॉरवर्ड मेसी, अपनी पत्नी एंटोनेला रोकुल्लों के साथ पहुंचे। उन्होंने होटल के बाहर प्रशंसकों से बातचीत की और ऑटोग्राफ दिए। यह सम्मान खेल हस्तियों को उनके शानदार करियर और अपने खेल के दायरे से बाहर किए गए योगदान के लिए दिया जाता है।

मेसी ने हाल ही में लिया था संन्यास

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को 2022 फुटबॉल विश्व कप का खिताब दिलाया था। इस साल भी अर्जेंटीना उनकी कप्तानी में फीफा विश्व कप में खेलने उतरी थी, लेकिन उसे फाइनल में स्पेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अर्जेंटीना को एक विश्व कप और दो कोपा अमेरिका का खिताब दिलाया। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 208 मैच खेले हैं और 126 गोल किए हैं। उनके नाम 68 असिस्ट भी हैं। वह अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। दो दशक से ज्यादा लंबे इस सफर में उन्होंने राष्ट्रीय टीम को चार बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई 2021 और 2024 कोपा अमेरिका, 2022 फाइनलिस्सिमा और सबसे बड़ा 2022 फीफा विश्व कप।



आइए, मिलकर अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करें।

विंग्स ओवर गेंजेस का सीधा प्रसारण जल महल पर 25 अक्टूबर को

राफेल, तेजस, मिराज सहित सूर्य किरण एरोबेटिक एवं सारंग हेलीकॉप्टर टीम होगी मुख्य आकर्षण का केंद्र



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। भारतीय वायुसेना के 94 वें स्थापना दिवस पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के नमो घाट पर होने वाले विंग्स ओवर गेंजेस एरियल डिस्प्ले का सीधा प्रसारण रविवार 25 अक्टूबर, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से जल महल जयपुर पर होगा।

एयर फोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ने बताया कि इस अवसर पर 100 एयरक्राफ्ट्स, 52 फाइटर्स 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 32 हेलीकॉप्टर्स और एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट 12 अलग अलग एयर बेसिस से उड़ान भरकर वाराणसी के नमो घाट के ऊपर हवाई प्रदर्शन करेंगे। इसमें राफेल, एसयू 30एम के 1,तेजस ,मिराज 2000, जैगवार ,एमआईजी -29 सहित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम व सारंग हेलीकॉप्टर टीम हवाई प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी।

राज निवेश पर सितंबर में 11,739.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज—मुख्य सचिव

अप्रैल से सितंबर तक 31,892 आवेदन स्वीकृत, छह माह में पिछले पूरे वित्त वर्ष से अधिक मंजूरियां

डीरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिविजन फेज-1 की सितंबर माह की मासिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट जारी

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बताया कि सितंबर, 2026 में राजनिवेश पर 11,739.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज हुए हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच 31,892 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। यह पिछले पूरे वित्त वर्ष में दी गई 29,536 स्वीकृतियों से अधिक है। उन्होंने ‘डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिविजन फेज-1’ की सितंबर, 2026 की मासिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में 4,840 करोड़ रुपये, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में 3,058 करोड़ रुपये, सौर उपकरण निर्माण में 1,000 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति क्षेत्र में 744 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज हुए। कुल प्रस्तावित निवेश राशि में इन चार क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग 82 प्रतिशत रही।

श्री श्रीनिवास ने बताया कि प्रथम चरण के सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में सुधार पूरे किए गए हैं। इनका उद्देश्य उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाना, अनुपालन का भार कम करना और सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना है। भूमि रूपांतरण की समयसीमा 90 से घटाकर 45 दिन की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम में स्थायी बिजली कनेक्शन के आवेदनों का निस्तारण समय 10 से घटकर 4 दिन और विधिक मापविज्ञान से जुड़े आवेदनों का समय 12 से घटकर 6 दिन रह गया है। राज निवेश की एकल खिड़की व्यवस्था पर 190 सेवाएं उपलब्ध हैं। अप्रैल से सितंबर, 2026 के दौरान 60,229 आवेदन प्राप्त हुए। पिछले पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में 34,704 आवेदन मिले थे। सर्वाधिक उपयोग वाली 10 सेवाओं के लिए 51,548 आवेदन प्राप्त हुए, जो कुल आवेदनों के करीब 86 प्रतिशत हैं। आवेदनों की निस्तारण दर अगस्त के 47 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 52 प्रतिशत हो गई।

जिलावार प्राप्ति की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि जयपुर 5,501 स्वीकृतियों के साथ अग्रणी रहा। इसके बाद जोधपुर में 2,577, अजमेर में 1,808, कोटा में 1,452 और हनुमानगढ़ में 1,238 स्वीकृतियां दी गईं। डीडवना-कुचामन, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर भी अग्रणी जिलों में शामिल रहे। रिपोर्ट में जिलावार आंकड़ों के आधार पर बाधाओं की पहचान कर सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।

पर्यावरण से जुड़े नियमों में सुधार के तहत श्वेत श्रेणी में शामिल गतिविधियों की संख्या 104 से बढ़ाकर 877 की गई है। रिपोर्ट में समयबद्ध मंजूरी, स्वप्रमाणन, जोखिम के आधार पर निरीक्षण, श्रम संबंधी लचीले प्रावधानों और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था जैसी पहलों का भी उल्लेख है।

मुख्य सचिव ने बताया कि रीको के भूमि आवंटन से जुड़ी परियोजनाओं में 1,080 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनसे लगभग 2,100 रोजगार अवसर बनने की संभावना है। पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने की प्रगति भी रिपोर्ट में शामिल है।

मुख्य सचिव कार्यालय के अधीन कार्यरत डीरेगुलेशन प्रकोष्ठ ने अलवर के रीको औद्योगिक क्षेत्रों की चुनिंदा इकाइयों का दौरा भी किया। इनमें स्वच्छ ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, पुनःचक्रण, कर्मचारी प्रशिक्षण, सुरक्षा अभ्यास और संसाधनों के बेहतर उपयोग की पहलों का अध्ययन किया गया।

डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिविजन फेज-1 की सितंबर, 2026 की विस्तृत मासिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट संलग्न है।

राज्यपाल से नव नियुक्त कुलगुरु प्रो. शिव सिंह सारंगदेवोत ने की शिष्टाचार भेंट



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे से शनिवार को लोकभवन में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा के नव नियुक्त कुलगुरु प्रो.शिव सिंह सारंगदेवोत ने मुलाकात की। कुलगुरु बनने के बाद प्रो. सारंगदेवोत की राज्यपाल से यह पहली शिष्टाचार भेंट थी।

दीपावली से पूर्व जगमग होगा अपना अजमेर -देवनानी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव ने किया शनिवार को इण्डिया मोटर सर्किल, ठठेरा चौक, ऊसरी गेट, शनि मन्दिर एवं शिव मन्दिर क्षेत्रों में हाईमास्ट लाइटों का शुभारम्भ

शहर के 80 वार्डों में लगेगी 3 हजार से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि दीपावली से पूर्व अजमेर शहर को रोशनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अजमेर उतर विधानसभा क्षेत्र में लाखों रुपये की लागत से चौराहों पर हाईमास्ट एवं मिनी हाईमास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही शहर के 80 वार्डों में 3 हजार से ज्यादा अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पुष्कर रोड़ एवं जयपुर रोड़ पर हैरीटेज पोल और हैरीटेज लाइटस् के जरिये सौंदर्योकरण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी



ने शनिवार को इण्डिया मोटर सर्किल, शनि मन्दिर, ठठेरा चौक, शिव मन्दिर और ऊसरी गेट क्षेत्र में हाईमास्ट लाइटों का शुभारम्भ किया। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 हाईमास्ट एवं 19 मिनी हाईमास्ट लाइटें तथा नगर निगम द्वारा 13 हाईमास्ट एवं 3 मिनी हाईमास्ट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम और एडीए को

निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली से पूर्व अजमेर उतर क्षेत्र में सभी सड़कों और चौराहों पर रोशनी के पर्याप्त इंतजाम हों। विभिन्न चौराहों पर हाईमास्ट व मिनी हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएं। वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाएं। हैरीटेज पोल व लाइट्स का काम पंद्रह दिन में पूरा कर लिया जाए। आवश्यकता वाले प्रमुख चौराहों पर हाईमास्ट एवं मिनी हाईमास्ट लाइटें लगाई

मंदिरा निर्माण इकाइयों को 12 घंटे चलाने के निर्देश, राजस्व में 15 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने वीसी के जरिए ली समीक्षा बैठक, मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर

द अनकवर्ड अपडेट

राजस्थान में मंदिरा निर्माण इकाइयों के उत्पादन, आपूर्ति और राजस्व की समीक्षा को लेकर आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने, जिलों की मांग के अनुरूप मंदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने और राजस्व में 15 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान आबकारी आयुक्त ने मंदिरा निर्माण इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों से पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन, आपूर्ति, राजस्व, बॉटलिंग फीस, आबकारी शुल्क और परमिट फीस की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही उत्पादन इकाइयों में आ रही समस्याओं और श्रमिकों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

12 घंटे तक संचालित होंगी निर्माण इकाइयां आबकारी आयुक्त ने कहा कि प्रदेश की कई मंदिरा निर्माण इकाइयां अपनी निर्धारित उत्पादन क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं। उत्पादन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इकाइयों को निर्धारित 12 घंटे की अवधि तक संचालित रखना सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं की स्थानीय स्तर पर समीक्षा कर उनका समाधान किया जाए।



उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इकाइयों में एक से अधिक उत्पादन लाइनें हैं, वहां जरूरत के अनुसार दूसरी उत्पादन लाइन भी शुरू की जाए, ताकि बाजार की मांग के अनुरूप आपूर्ति में कमी नहीं आए। **जिला आबकारी अधिकारियों को भी दिए निर्देश**

बैठक में संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को मंदिरा निर्माण इकाइयों की समस्याओं की समीक्षा कर उनका समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित

करने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ काम करने को कहा।

इस दौरान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत ने भी मंदिरा निर्माण इकाइयों से उत्पादन और आपूर्ति की विस्तृत जानकारी ली।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (जोन), जिला आबकारी अधिकारी और मंदिरा निर्माण इकाइयों के प्रभारी आबकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

पंचायतीराज आम चुनाव

पंच व सरपंच के चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न, कुल 88.09 प्रतिशत मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की मतदान केंद्रों पर प्रभावी निगरानी, विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं

द अनकवर्ड अपडेट

फ्लौदी। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत पंच व सरपंच के मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हुए। जिले की 9 पंचायत समितियों की 274 ग्राम पंचायतों के 492223 मतदाताओं में 433592 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मतदान प्रतिशत 88.09 रहा। 31 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हुआ।

6 बजे मतदान प्रतिशत के अनुसार पंचायत समिति फ्लौदी की 34 ग्राम पंचायतों के 67155 मतदाताओं में 60212 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 89.66 रहा। पंचायत समिति आऊ की 20 ग्राम पंचायतों के 42743 मतदाताओं में 37364 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 87.42 रहा। पंचायत समिति बाप की 52 ग्राम पंचायतों के 86888 मतदाताओं में 78857 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 90.76 रहा।

पंचायत समिति बापिणी की 26 ग्राम पंचायतों के 49845 मतदाताओं में 42693 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.65 रहा। पंचायत समिति देचू की 21 ग्राम पंचायतों के 35698 मतदाताओं में 30547 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.57 रहा। पंचायत समिति घंटियाली की 37 ग्राम पंचायतों के 71204 मतदाताओं में 62724 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 88.09 रहा।



पंचायत समिति लोहावट की 40 ग्राम पंचायतों के 67607 मतदाताओं में 60334 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 89.24 रहा। पंचायत समिति पीलवा की 24 ग्राम पंचायतों के 38465 मतदाताओं में 33041मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.90 रहा। पंचायत समिति सेतरावा की 20 ग्राम पंचायतों के 32618 मतदाताओं में 27820 मतदाताओं ने मतदान किया तथा मतदान प्रतिशत 85.29 रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान केंद्रों का औपक निरीक्षण :-

मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक

आदित्य काकड़े ने मतदान केंद्र खींचन,पलीना, मोटाई, जाम्भा की ढाणी, चाखु, चिमाणा, जैसला, नोखड़ा, भाटियान, भोजासर, आसोलाई, बरजासर, सजनानियों की ढाणी, ढेलाना, छीला, लोईया का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर तैनात मतदान दलों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी गई। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया।

जाएं। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में आवश्यकता के अनुसार करीब 3 हजार नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि अजमेर नगर निगम को निर्देश दिए गए थे कि दीपावली से पहले लोहाखान टैम्पो स्टैण्ड, इंडिया मोटर्स सर्किल, शनि मंदिर वैशाली नगर, लवकुश गार्डन, पसंद नगर कोटड़ा, शिव मंदिर रेम्बल रोड, ऊसरी गेट, ठठेरा चौक, पंचोली चौराहा व अन्य क्षेत्रों में हाईमास्ट व मिनी हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएं। ऋषि उद्यान से अंद्रेत आश्रम तक निगम द्वारा हैरीटेज लाइट व डेकोरेटिव पोल लगाए जाएं। इसी तरह सर्किट हाउस व जयपुर रोड़ पर भी नगर निगम लाइटें लगवाई जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेरिटेज लाइटिंग का शेष कार्य आगामी 15 दिनों में पूरा कर लिया जाए। इन सभी निर्देशों पर लगातार काम जारी है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि एलीवेटेड रोड के नीचे त्र्योहार पर आकर्षक लाईटिंग की जाए। शहर के 80 वार्डों में निगम द्वारा 3 हजार से अधिक लाइटें लगाई जाएगी। उन्होंने कहा

कि शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ रात्रिकालीन यातायात एवं सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था आवश्यक है।

विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि पुष्कर रोड़ पर डेकोरेटिव पोल व हाईमास्ट लाइट का काम भी दीपावली से पहले पूर्ण हो। इसी तरह योजना क्षेत्रों में सभी लाइटों की जांच हो एवं बंद लाइटों को चालू कराया जाए। एडीए क्षेत्र की हाइमास्ट लाइटें व मिनी हाईमास्ट लाइटें चालू रखी जाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले सभी आवश्यक प्रकाश व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर किया जाए। खराब एवं बंद स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के साथ जरूरत वाले स्थानों पर नई लाइटें लगाई जाएं। उन्होंने निगम एवं एडीए अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर श्रीमती अनामिका शर्मा, पार्षद श्री अनीश गोयल, श्री प्रवीण जैन, श्री अरविंद यादव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान में स्वच्छ-सुलभ सार्वजनिक परिवहन को पीएम ई-बस से मिल रही नई गति

राज्य के 9 शहरों के लिए 1150 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत, अब तक मिली 250 ई-बस

जयपुर को अब तक मिली 103 ई-बस, 450 ई-बसें और

50 डबल डेकर ई-बसें प्राप्त करने की चल रही प्रक्रिया

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम ई-बस सेवा योजना देश के शहरी परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव का आधार बन रही है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रारंभ में राजस्थान के आठ शहरों के लिए कुल 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई थी। परंतु राज्य सरकार के विशेष प्रयासों और मजबूत प्रबंधन के चलते प्रदेश के लिए अतिरिक्त बसें स्वीकृत कराई गई हैं, जिससे राजस्थान के लिए कुल 1150 ई-बसें मंजूर हो चुकी हैं। जयपुर के लिए 550, जोधपुर के लिए 125, अजमेर एवं कोटा के लिए 100-100, बीकानेर के लिए 75, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और सीकर के लिए 50 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं। राज्य को अब तक 250 ई-बसें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 103 बसें जयपुर के लिए जेसीटीएसएल को मिली हैं। 58 बसों का संचालन बगराना डिपो से किया जा रहा है जबकि शेष बसों का संचालन टोडी डिपो से शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

सीसीटीवी, पैनिंक बटन जैसी तकनीकों से सुसज्जित हैं ई-बसें

अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित ये ई-बसें वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों और दिव्यांगजनों के लिए किफायती और आरामदायक सफर सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं, बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे, पैनिंक बटन और सुरक्षा उपकरणों से महिला सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

डिपो एवं चार्जिंग इन्फ्रा विकसित करने पर फोकस

बजट घोषणा 2025-26 की अनुपालना में बाकी 450 ई-बस और 50 डबल डेकर ई-बस प्राप्त करने की प्रक्रिया जेसीटीएसएल द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बसों की खरीद और उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी संपूर्ण व्यवस्था तैयार करने पर है, जिससे बसों का नियमित संचालन हो और यात्रियों को सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा मिल सके।

इसी दिशा में सरकार द्वारा बसों की उपलब्धता के साथ-साथ बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, विद्युत कनेक्शन और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जयपुर में बगराना, टोडी मोड़ और सांगानेर में ई-बसों के सुगम संचालन के लिए डिपो बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त गोनेर के नजदीक रलावात, अजमेर रोड पर खटवाड़ा और दिल्ली रोड पर अचरोल में डिपो के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है। बस डिपो में चार्जिंग एवं अन्य विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक एवं बस डिपो का सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 53 करोड़ रुपये से अधिक की राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

चूरू में हुए सड़क हादसे पर राज्यपाल की शोक संवेदना

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने चूरू के सादुलपुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने के शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।